रपट

बिहार के आदिवासी आवासीय स्कूल

❑ वासवी

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की सूची में बिहार सबसे नीचे है । राज्य में आदिवासी समाज शिक्षा-सुविधाओं से हाल तक वंचित हैं और आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा धारा से जोड़ना तो एक भागीरथी प्रयत्न है । ऐसे में आदिम जनजाति के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रावधान है । किन्तु इन आवासीय विद्यालयों की बदहाली और घर से दूर बालिकाओं का असुरक्षा और असुविधाओं के बीच निरंतर जूझना शिक्षण-प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित करता है।

आदिम जनजातियों के बच्चों के जीवन का अंधेरा मिटाने और उन्हें ज्ञान की रोशनी से सराबोर करने की सरकारी योजनाएं दम तोड रही हैं । संताल परगना में पहाड़िया बच्चों के आवासीय स्कूलों की खस्ता हालत ने जनजातीय कल्याण आयुक्त दफ्तर को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है । खस्ता भवन, भूखे बच्चे और शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से वंचित पहाडिया बच्चों के स्कूल बिहार सरकार के कल्याण विभाग को बेनकाब करते हैं । संताल परगना के गोड्डा, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ के जनजातीय स्कूलों के अध्ययन ने सरकार का भंडाफोड़ कर दिया है । साथ ही उन आदिवासी नेताओं का भी जो अपने लोगों के हितों की बात करते हैं । अध्ययन में पाया कि पहाड़िया बच्चे भूख और गरीबी से ही स्कूलों में पढ़ने और आवासीय विद्यालयों में रहने को आते हैं । लेकिन जब उनकी भूख नहीं मिटती और ज्ञान हासिल नहीं होता तो वे जंगल की ओर लौट जाते हैं । यही कारण है कि जनजातीय बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उनसे इन बच्चों के जीवन में हरियाली नहीं लाई जा सकी । दस सालों में स्कूलों के मैट्रिक परीक्षाफल में कभी भी शत-प्रतिशत छात्र उर्त्तीर्ण नहीं हुए। कहीं कहीं तो एक भी छात्र ने परीक्षा पास नहीं की ।

बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने संताल परगना के पंद्रह स्कूलों का अध्ययन कर कई आश्चर्यजनक बातें उजागर की हैं । संस्थान के अध्ययनकर्ता विजयपाणि पांडेय ने अध्ययन में बताया कि सरकार ने 1953 में आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन आज तक इसे संताल परगना के सभी आदिवासी स्कूलों में लागू नहीं किया जा सका है । इस कारण दूसरी भाषा में पहाड़िया बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते । स्कूल छोड़ने के कई कारणों में यह एक प्रमुख कारण है । अध्ययन में यह बात सामने आई कि कल्याण विभाग से करोड़ों रुपये की राशि आवंटन के बावजूद पेड़ों के नीचे स्कूल चलाए जा रहे हैं। शिक्षकों के रहने के लिए आवास नहीं है औसत 88 छात्रों के लिए मात्र 50 चौकी हैं, जिसमें वे किसी तरह से सोते हैं ।

बच्चों के स्कूल छोड़ने की एक वजह कम उम्र में ही विद्यालय में अपने अपने जीवन साथी की तलाश कर स्कूल छोड़ देना भी है। आसन पहाड़ी गांव में यहां के विद्यालय की छह लड़कियां बहू बन कर रह रही हैं, जबकि वे कक्षा पांच, सात, आठ-नौ और दस की छात्रा हैं । आवासीय विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी, विद्यालय भवन, छात्रावास, सोने की चौकी, शौचालय, भोजनालय, स्नानागार, शिक्षक आवास, खेल और मनोरंजन के साधन, भोजन के बर्तन, उपस्कर, कुर्सी-मेज डेस्क, नियमित चिकित्सा सुविधा, छात्रों के लिए मच्छरदानी, दरी और छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि जागृत करने के लिए संसाधनों की कमी पाई गई । आवासीय विद्यालय मूल उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं और बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं। आवासीय स्कूलों में शिक्षा गौण हो गई है, भोजन व वस्त्र के मसले पर ही शिक्षक और छात्र-छात्रा उलझे रहते हैं ।

अध्ययन में बताया कि संताल परगना के 32 आवासीय विद्यालयों में से अध्ययन के लिए 15 विद्यालयों का चयन किया गया । सरकारी योजना के तहत संताल परगना में चार बुनियादी शिक्षा विद्यालयों की स्थापना की गई । इनमें गोडडा जिले में सुंदर पहाड़ी के धमनी गांव, साहेबगंज के बोरियों प्रखंड के बांझी गांव, पाकुड़ जिला के लिटिपाडा प्रखंड के हिरणपुर गांव और दुमका जिला के गोपीकांदर प्रखंड के गोपीकांदर गांव में ये विद्यालय चलाये जा रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में और शिक्षा के मूल उद्देश्यों से दूर ।

1976 में आदिम जनजातियों के आवासीय विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में बदल दिया गया । संताल परगना में विद्यालयों की संख्या 32 है । इनमें 6 उच्च विद्यालय, 26 मध्य और प्राथमिक विद्यालय हैं । दुमका जिले में 14, गोडडा में सात, साहेबगंज जिला में आठ और पाकुड़ जिला में तीन आवासीय विद्यालय हैं । संताल परगना में तीन प्रमुख जनजातियां रहती हैं । संतला, माल और सोरिया पहाड़िया । माल और सौरिया पहाड़िया बिहार में आठ आदिम जनजातियों में से एक हैं । सौरिया पहाड़िया संताल परगना के राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करती हैं ।

अध्ययन में बताया गया है कि विद्यालयों में सेवारत प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कल्याण विभाग की ओर से होती है । इसमें ऐसे लोग भी है जो कि कल्याण विभाग के अधिकारियों की पत्नियां हैं। विषयवार शिक्षकों की प्रोन्नति और बहाली नहीं की जाती है कि उक्त शिक्षक विषय का जानकार है या नहीं । जिन शिक्षकों को प्रोन्नति दी जानी चाहिए उन्हें अब तक नहीं दी गई है । शिक्षकों के तबादले में कल्याण विभाग के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जाता । कई शिक्षक तो एक विद्यालय में कई सालों से पदस्थापित है । किसी भी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के रहने के लिए आवास की उचित व्यवस्था नहीं है । गांव में किसी के घर पर एक कमरा लेकर शिक्षक रहते हैं या फिर पास के शहर कस्बों में रहने के लिए जाते है। ऐसे में उन्हें विद्यालय पहुंचते 11 से 12 बज जाते हैं, फिर वापसी के लिए बस पकड़ने की जल्दी होती है । शिक्षा आयोग की अनुशंसा के बावजूद जनजातीय शिक्षकों को विशेष वेतनमान नहीं मिलता।

शिक्षा को पहाडिया लोगों के जीवन के अनुकूल बनाने, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए कदम उठाने, शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने, लोक संगीत और लोक कला को शिक्षा में महत्वपूर्ण बनाने की अनुशंसा की गई लेकिन अब तक इन अनुशंसाओं पर पानी ही फिरता आया है।

विद्यालय के भवनों और छात्रावासों की हालत बेहद ही दयनीय पाई गई । दुमाका जिले के शिकारी पाडा में पहाड़िया आवासीय विद्यालय किराए के खपरैल में चलाया जा रहा है । इसमें 88 छात्रों के लिए दो कमरे हैं । एक किनारे जलावन की लकड़ी रखी थी । शिक्षण कार्य पेड की छाया में हो रहा था। गर्मी और बरसात में अध्यापन का कार्य ठप्प हो जाता है । छात्रावास में चौकी नहीं होने की वजह से छात्र जमीन पर ही सोते हैं । शिक्षण सामग्री की कमी है । दुमका जिला में ही कैराबनी के पहाड़िया जाति बालिका विद्यालय के लिए दो कमरे हैं जो कि किराए के मकान में चल रहे हैं । दो कमरों में एक भंडार है और दूसरा विद्यालय सह छात्रावास। इसमें ही 88 छात्राएं किसी तरह पढ़ती हैं । गोड्डा जिला में पहाड़िया बालिका विद्यालय चांदना में है । यहां भी 88 छात्राओं को रहने के लिए किराए पर दो कमरे और बरामदा है । छात्राएं जमीन पर दरी बिछाकर सोती है । शौचालय और स्नानागार नहीं है । रसोई भी इसी कमरे में है।

खाना बनता है तो पूरा कमरा धुएं से भर जाता है । विद्यालय के बाहर एक चाापाकल है जहां से छात्राएं पानी लाती हैं । नहाने के लिए छात्राओं को दो किलोमीटर दूर नदी में जाना पडता है ।

साहेबगंज के बोरियो प्रखंड के बंदरकोला बालिका उच्च विद्यालय के भवन और छात्रावास भवन दोनों हैं । लेकिन बरसात के दिनों में टपकने की वजह से कोई पढ़ाई नही हो पाती है। गोड्डा जिला के ही सुंदरपहाडी प्रखंड के गम्हारो आवासीय विद्यालय को 1990 में स्थापित किया गया । तब से यह विद्यालय फूस की छत वाले भाडे के दो कमरों में ही चलाया जा रहा है। इसका उपयोग शिक्षण कार्य, पाकशाला और छात्रावास के तौर पर किया जाता है। गोडा जिला के बोआरीजोर प्रखंड के कोरटिका मध्य विद्यालय गांव में ही भाडे के कमरे में चलाया जाता है । लेकिन अब इसे गांव के बाहर पंचायत भवन और बिहार सरकार के प्राथमिक विद्यालय में चलाया जाता है । 88 बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था है ही नहीं। छात्राएं कोरटिका गांव जाकर सोती हैं । आवासीय विद्यालय में 248 छात्राओं के नामांकन का प्रावधान है । लेकिन यहां छात्रावास में मात्र 48 छात्राओं के रहने की ही व्यवस्था है । बाकी छात्राएं दरी बिछाकर जमीन पर ही सोती है। विद्यालय परिसर में शौचालय, स्नानघर, भोजनालय, पाकशाला का अभाव है ।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य मद में दवा वगैरह के लिए आवासीय विद्यालय में प्रति छात्र 50 रुपये का प्रावधान किया है। यह अपर्याप्त राशि है । सुदूर पहाडों और जंगल के बीच रहने वालों के लिए आवागमन की सुविधा नहीं होने से इस पैसे से इलाज संभव ही नहीं है । विद्यालयों के छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं होती । आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करने कल्याण विभाग के अधिकारी आते हैं । लेकिन वे भंडार घर सामान के स्टाक पंजी और छात्रों के भोजन के बारे में ही पूछते हैं । शिक्षा के स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते हैं ।

उच्च विद्यालय के छात्रों को कक्षा दस में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठना पड़ता है। उसके पहले अपने विद्यालय की परीक्षा में 90 प्रतिशत तक छात्र उत्तीर्ण होते हैं । लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में एक से दो प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो पाते हैं । इसका मतलब है कि आंतरिक परीक्षा में छात्रों की पुस्तकाओं की जांच ठीक ढंग से नहीं की जाती है। इसका कारण है विषयवार शिक्षकों का अभाव और शिक्षा के प्रति छात्रों की अरूचि ।

इन आवासीय विद्यालयों में वैसे शिक्षकों को पद्स्थापित कर दिया गया है जो इस क्षेत्र के निवासियों की संस्कृति और परंपरा से ही अनभिज्ञ हैं । शिक्षक और छात्रों के बीच इस वजह से बहुत दूरी है और शिक्षक छात्रों की मानसिकता को समझ ही नहीं पाते । छात्रों में यह भावना घर कर गई है कि उनके लिए मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था है । इसे वे अब अपना अधिकार समझने लगे हैं । शिक्षा ग्रहण करने के प्रति वे धन नहीं देते हैं । बांझी, साहेबगंज, धमनी, गोडडा, हिरणपुर, पाकुड के प्रधानाध्यापकों ने

बताया कि छात्रों ने कई बार शिक्षकों के साथ मारपीट की है । इससे शिक्षा पर बुरा असर पडा है । छात्राओं में अनुशासनहीनता ऊंची कक्षाओं में ही है । छात्र अपने गांव घर के दोस्तों को भी छात्रावास में रखते हैं। उनके लिए निर्धारित भोजन को वे दोस्तों को छात्रावास के भीतर ले जाकर खिलाते हैं । कोई भी शिक्षक छात्रावास अधीक्षक बनना नहीं चाहता । शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का मानना है कि छात्रों का राजनीतिकरण होने की वजह से ही उनमें अनुशासनहीनता आ गई है । विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इन छात्रों का उपयोग प्रदर्शन और जुलूसों में करती हैं और भीड बढ़ाने के लिए इन्हें ले जाती हैं ।

आवासीय विद्यालय के अध्ययन में पाया कि छात्रों को सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है । छात्र देश के नायकों, महापुरुषों और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी हासिल करने को उत्सुक लगे। विद्यालयों में शैक्षणिक यात्रा के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है । नकटी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि 1994 तक एक भी स्नातक पास शिक्षक की पद स्थापना उच्च वर्ग के लिए नहीं की गई । अभी भूगोल, गणित, हिंदी, स्नातक शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो पाई है । इसी तरह अंग्रेजी, संस्कृत, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय विशेषज्ञ स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है । इसका सीधा असर शिक्षा पर पडता है । इस बालिका विद्यालय में स्नानघर, पेशाबघर, पखानाघर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लड़कियां झरने, तालाब, नदी और गड्ढे में स्नान करने जाती हैं । समय-समय पर असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें तंग किया जाता है ।

छात्रावास में 248 छात्राओं को रखने की व्यवस्था है । 1997 में 241 छात्राएं वहां रह रही थीं, लेकिन इस समय 48 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है । चौकी के अभाव में लड़कियां जमीन पर सोती हैं । कक्षा में डेस्क की कमी है । छात्रों को जमीन पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता है । छात्राएं मात्र भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुएं पाने के लालच में ही छात्रावास में रहती हैं । पहली कक्षा में पचास छात्राएं नामांकन कराती हैं । लेकिन यह संख्या दसवीं कक्षा तक आते आते सात आठ रह जाती है । अध्ययन में बताया गया है कि साहेबगंज के बोरियो प्रखंड के चांदवासी स्कूल की स्थापना 15 मार्च, 1990 को हुई थी । इसे नया भवन 1997 में बनाकर साहेबगंज दुमका मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया । दो मंजिले भवन में 15 कमरे हैं । इस विद्यालय में शिक्षकों के सात स्वीकृत पद हैं । इसमें अभी दो शिक्षक हैं । दो-दो अनुसेवक और रसोईया है ।

जनजातीय मध्य विद्यालय अरगौरी साहेबगंज की स्थापना भी 1990 में हुई थी । यहां भी शिक्षकों के सात पद स्वीकृत हैं, लेकिन तीन शिक्षक ही कार्यरत है। इस विद्यालय में 88 स्थान स्वीकृत हैं, लेकिन अध्ययन के दौरान सात लडके ही उपस्थिति मिले । यहां 88 छात्रों के लिए पचास चौकी हैं । ऐसे में कुछ छात्रों को बगल के घर में सुलाया जाता है । स्कूल में बच्चों और यहां तक कि पीने के पानी के लिए गिलास तक नहीं हैं । बीमार होने पर प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराना पडता है ।

तमाम विद्यालयों में पठन पाठन सामग्री का अभाव पाया है। साहेबगंज के बोरियो प्रखंड के बंदलकोला बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना 1982 में की गई। 11 लाख रुपये की लागत से इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण का काम किया गया, लेकिन इसमें भी दो कमरे अर्द्धनिर्मित हैं । आठ कक्षाओं में से केवल दो में श्यामपट्ट है । विद्यालय भवन में न तो खिड़की है और न ही दरवाजे। पूरा भवन ही खस्ता हालत में है। इस विद्यालय को बनाने के लिए पहाडिया महेंन्द्र मालतो ने तीन एकड जमीन दान में दी थी।

गोडा का धमनी उच्च विद्यालय 15 एकड भूमि में फैला हुआ है । यहां शिक्षकों के 17 पद स्वीकृत हैं लेकिन अभी 12 ही कार्यरत हैं । इस विद्यालय में कुर्सी मेज और बेंच ही नहीं है । जमीन पर बैठकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं । इस विद्यालय में हिंदी शिक्षक गणित की और संस्कृत के शिक्षक अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं । विद्यालय में तीन सौ छात्रों के पद स्वीकृत हैं लेकिन 270 छात्र ही उपस्थित मिले । यहां के छात्रों ने प्रधानाध्यापक की दो बार पिटाई कर दी । छात्रों के बारे में शिक्षक कहते हैं कि छात्र उन्हें केवल खाने और सोने की सुविधा देने की बात कहते हैं । इसमें कमी होने पर मारपीट करते हैं । इस विद्यालय में मनोरंजन का कोई साधन नहीं है । विद्यालयों में सफाई की स्थिति खराब है। छात्रों को साबुन दिया जाता है तो वे कभी कभी नहाते हैं । रसोई बहुत ही गंदी है ।

अध्ययन के बाद आदिम जनजाति के बच्चों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए तत्काल व्यवस्था करने की अनुशंसा की गई है । संताल परगना के आवासीय विद्यालयों में छात्रों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने, शिक्षण कार्य पर जोर देने, पहाडिया बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक पैदा करने, शिक्षक और छात्र के बीच दूरी कम करने, जनजातीय संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा की व्यवस्था करने, विषयवार शिक्षकों की बहाली करने, बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने, शैक्षणिक यात्रा की व्यवस्था करने, परीक्षाफल कम से कम 75 प्रतिशत तक करने, छात्रों को भोजन के कार्य में न लगाने की अनुशंसा की गई है । शिक्षा को पहाडिया लोगों के जीवन के अनुकूल बनाने, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए कदम उठाने, शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने, लोक संगीत और लोक कला को शिक्षा में महत्वपूर्ण बनाने की अनुशंसा की गई लेकिन अब तक इन अनुशंसाओं पर पानी ही फिरता आया है ।◆